

देर से घर से निकलने और लंबा रास्ता लेने के कारण छात्रा नीट परीक्षा से चूकी : बेंगलूर यातायात पुलिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। बेंगलूर यातायात पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसकी 'तथ्यान्वेषी जांच' से पता चला है कि एक छात्रा 21 जून को आयोजित नीट परीक्षा में देर से घर से निकलने और अपेक्षाकृत लंबा मार्ग चुनने के कारण शामिल नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि यह निष्कर्ष सीसीटीवी फुटेज, आर.टी. नगर क्षेत्र की अभ्यर्थी और उसके अभिभावकों से बातचीत तथा मार्ग विश्लेषण के आधार पर निकाला गया है। यातायात पुलिस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि सीसीटीवी विश्लेषण और मार्ग सत्यापन से यह स्थापित हुआ है कि नीट अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद परीक्षा केंद्र पहुंची थी।

पुलिस ने कहा, 'यातायात की स्थिति सामान्य पाई गई और आवश्यकता पड़ने पर यातायात पुलिस कर्मियों ने आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की। परीक्षा केंद्र के मुख्य कारण घर से देर से निकलना और मार्ग का चयन था।' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ सरकार पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि बेंगलूर यातायात पुलिस द्वारा नीट अभ्यर्थी की देरी को लेकर जारी 'तथ्यान्वेषी जांच' रिपोर्ट कांग्रेस सरकार की ओर से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके खुद को जन्ता के गुप्से से बचाने की 'बेहद निराशाजनक' कोशिश है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बेशर्मा और असंवेदनशील बताया है। भाजपा ने कहा कि जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटका है, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय प्रशासन अपनी सारी ऊर्जा एक परेशान अभ्यर्थी के आने-जाने के तरीके का बारीकी से विश्लेषण करने में लगा रहा है। तथ्यान्वेषी जांच का विवरण साझा करते हुए पुलिस ने बताया कि अभ्यर्थी दोपहर 12 बजकर 57 मिनट पर आरटी नगर स्थित अपने

मानसून की कमी से 111 जिलों में फसल नुकसान का सबसे ज्यादा खतरा : सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने 111 जिलों की पहचान की है जहां फसल को सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा है, क्योंकि अल नीनो के कारण मानसून में 43 प्रतिशत की कमी खरीफ की बुवाई को प्रभावित कर रही है।

चौहान ने कहा कि मानसून की कमजोर स्थिति दो जुलाई तक बने रहने की संभावना है, जिससे किसानों के पास खरीफ (गर्मी) की फसल बोने के लिए बहुत कम समय बचेगा। 22 जून तक, खरीफ फसलों की बुवाई कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के 10 प्रतिशत से भी कम हिस्से में हुई है, जो पिछले साल की इसी अवधि में दर्ज एक करोड़ 17.9 लाख हेक्टेयर की तुलना में थोड़ा अधिक यानी एक करोड़ 19.9 लाख

हेक्टेयर है। और सोयाबीन को छोड़कर ज्यादातर फसलें आगे चल रही हैं।

मानसून की प्रगति पर समीक्षा बैठक के बाद चौहान ने पत्रकारों से कहा, 'कुल मिलाकर, मानसून की बारिश में 43 प्रतिशत की कमी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कमजोर मानसून दो जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि खरीफ फसलों पर असर पड़ सकता है।' मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 315 जिलों की पहचान की है, जहां सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इनमें से 111 जिलों में जून 2026 के 20 जिले शामिल हैं जिनमें महाराष्ट्र के 20 जिले शामिल हैं जिनमें 'सबसे ज्यादा जोखिम वाले' जिलों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि वहां सिंचाई की सुविधा 25 प्रतिशत से कम है। 25-50 प्रतिशत सिंचाई सुविधा वाले 76 जिले 'मध्यम



जोखिम' वाली श्रेणी में आते हैं, जबकि पर्याप्त बांध और सिंचाई बुनियादी ढांचे वाले 128 जिलों को 'सबसे कम जोखिम' वाला माना गया है। मंत्रालय ने राज्य-वार आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं, जिनमें काम बारिश की स्थिति के अनुकूल वैकल्पिक फसलों की सिफारिश की गई है।

राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे कम पानी की जरूरत वाली दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों को बढ़ावा दें और किसी एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय कम समय में तैयार होने वाली और जलवायु के अनुकूल बीजों की किस्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें।

मंत्री ने कहा, 'बारिश में कमी है। हमें किसानों को वैकल्पिक फसलें अपनाने का सुझाव देने की जरूरत है। हम खेतों को खाली नहीं रहने देंगे।' उन्होंने कहा कि इस सत्र के लिए बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। जलाशयों में पानी का स्तर अभी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, हालांकि इसमें कमी आ रही है। राज्यों से कहा गया है कि वे पानी का समझदारी से इस्तेमाल करें और सिंचाई की जरूरतों के लिए पानी बचाने के मकसद से वीबी-ग्राम जी (विकसित भारत जगजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण) कार्यक्रम के तहत तालाबों, नदियों, खेतों के तालाबों

और चेक डैम की सफाई करें। मंत्रालय ने बुनियादी राज्यों में फसल बीमा योजनाओं और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण करने को कहा है। 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) से कहा गया है कि वे किसानों तक अपनी पहुंच बढ़ाएं और एसएमएस, व्हाट्सएप, कॉल सेंटर व अन्य माध्यमों से समय-समय पर सलाह पहुंचाएं।

उत्पादन के अनुमानों पर चौहान ने कहा कि ये अनुमान सामान्य स्थितियों पर आधारित हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया, 'हम यह पक्का करेंगे कि उत्पादन में कोई कमी न आए।'

मंत्रालय ने वास्तविक समय पर निगरानी और सलाह देने के लिए एक 'अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ' और 'क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप' बनाया है। संवाददाता सम्मेलन में कृषि सचिव अतिश चंद्र, आईसीएआर के महादेशिक एमएल जाट और कृषि आयुक्त पीके सिंह भी मौजूद थे।

कर्णप्रयाग, नगरासू घटनाओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है : मुख्यमंत्री धामी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

देहरादून/भाषा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि कर्णप्रयाग और नगरासू में सामने आई घटनाओं के संबंध में निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ यहां हुई उच्चस्तरीय बैठक में कहा, 'सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, प्रशासन और पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और तथ्यों के आधार पर

आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।'

धामी ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है कि देवभूमि में ऐसा कोई कृत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा या किसी धर्म और आस्था को ठेस पहुंचे।

कर्णप्रयाग में 16 जून को स्थानीय लोगों और निहंग सिखों के बीच मामूली विवाद के दौरान कथित तौर पर तलवार से किये गये हमले में कुछ लोग घायल हो गए थे। घटना में एक निहंग सिख भी घायल हुआ था।

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चार निहंग सिखों को

गिरफ्तार किया था। कर्णप्रयाग घटना में गिरफ्तार निहंगों की रिहाई की मांग को लेकर 20 जून की शाम कुछ निहंग रुद्रप्रयाग जिले के बदरीनाथ राजमार्ग स्थित नगरासू गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए थे और छत पर जाने का झर बंद कर दिया था।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी भद्रालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

धामी ने उत्तराखंड को आस्था, संस्कृति और प्रकृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए भद्रालुओं और पर्यटकों से अपील

की कि वे देवभूमि के शांत वातावरण में अपनी यात्रा का आनंद लेते तथा किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

धामी ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वाले लोगों को खतरे वाले क्षेत्र में बांटने वाले प्रयासों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि भ्रामक और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, हेमकुंड साहिब प्रबंधन दूर के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा और बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी मौजूद थे।



दिल्ली: तकिया काले खां में आग लगने से 30 झुगियां जलकर खाक, पुलिस ने 12 लोगों को बचाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। मध्य दिल्ली के तकिया काले खां इलाके में आग लगने से कम से कम 30 झुगियां जलकर खाक हो गईं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया और पुलिस ने 12 लोगों को खतरे वाले क्षेत्र से बाहर निकाला। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने का सही कारण अब पता नहीं चल पाया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, सोमवार रात 11.22 बजे आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की 24 गाड़ियों को मौके पर

भेजा गया। अधिकारी ने कहा कि दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में लगभग तीन घंटे लगे।

डीएफएस ने कहा कि सोमवार देर रात 12.55 बजे तक आग बुझा दी गई, जिसके बाद शीतलन अभियान चलाया गया।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आग उस क्षेत्र में लगी जहां पुराना फर्नीचर, लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी, जिसके चलते घना धुआं फैल गया और दशहत्त पैदा हो गई कि आग आसपास के घरों में भी फैल जाएगी। अधिकारी ने कहा, टीकों ने घर-घर जाकर निकासी की और परिवारों को प्रभावित क्षेत्र से दूर जाने के लिए राजी किया। समय पर हस्तक्षेप से, आग को फैलने से पहले टीकों ने 12 लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया।

सूरत में बुजुर्ग दंपति ने इच्छा-मृत्यु की मांग की, अधिकारियों पर 'आर्थिक उत्पीड़न' का आरोप लगाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सूरत/भाषा। गुजरात के सूरत शहर में एक बुजुर्ग जोड़े ने नगर निकाय के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं पर उनका आर्थिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए इच्छा-मृत्यु की इजाजत मांगी है। श्याम गहलोत (73) और उनकी पत्नी मधु (68) ने हाल में अपनी दुकानें सील किए जाने के बाद सूरत के जिलाधिकारी तेजस परमार को पत्र लिखकर इच्छा-मृत्यु की इजाजत देने की मांग की है।

नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि दंपति की 11 दुकानों को सील कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें गुजरात अनधिकृत विकास नियमितिकरण (जीआरपीडी) अधिनियम, 2022 के तहत

नियमित करवाना जरूरी है। अधिकारी के मुताबिक, दुकानों के नियमितिकरण के लिए दंपति को कुछ दरतायेज जमा करने होंगे। गहलोत दंपति ने जिलाधिकारी को 19 जून को लिखे पत्र में कहा, सूरत नगर निगम के उधन दक्षिण जिन के कार्यकारी अभियंता और कुछ राजनीतिक हस्तियों की ओर से लगाए गए जा रहे असहनीय शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के कारण इच्छा-मृत्यु की अनुमति देने का अनुरोध है। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले गहलोत दंपति ने साल 2016 में एक हादसे में अपने परिवार के नौ सदस्यों को गंवा दिया था। वे अब सूरत के पांडेयारा इलाके में रहते हैं। दंपति ने बमरोली ग्राम पंचायत में अलग-अलग भूखंड पर 12 दुकानें खरीदी थीं, जो बाद में सूरत नगर निगम (एसएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आ गईं।

दक्षिण दिल्ली में फुटपाथ से बच्ची का अपहरण, बलात्कार और फिर हत्या, कैब चालक गिरफ्तार

नई दिल्ली/भाषा। दक्षिण दिल्ली के महरोली इलाके में अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही 11 साल की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और फिर उसे मार डाला गया।

एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कैब चालक ने जूम छिपाने की कोशिश में उसके शव को फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड के किनारे एक जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के छह घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। महरोली में फुटपाथ पर रहने वाले परिवार को सोमवार सुबह लड़की नहीं मिली तब उन्होंने उसे खोजना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक, बच्ची को सुबह करीब 4:15 बजे फुटपाथ से कथित तौर पर अगवा कर लिया गया, जब वह सो रही थी। थोड़ी देर बाद उसके पिता की नींद खुली तो उन्होंने एक सफेद कार को जाते हुए देखा और उन्हें पहचाना हुआ कि लड़की वहां नहीं है। परिवार के सदस्यों ने सुबह करीब 4:58 बजे पुलिस को फोन किया, और पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और पुलिस ने लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपी करीब 30 साल का कैब चालक है और बिहार का रहने वाला है।

एफसीएनआर (बैंक) अदला-बदली सुविधा में केवल मूलराशि शामिल, ब्याज नहीं : आरबीआई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि विदेशी मुद्रा प्रवासी जमा (एफसीएनआर) के लिए अदला-बदली सुविधा एक साधारण विदेशी मुद्रा अदला-बदली है लेकिन इसमें केवल मूल राशि शामिल है, ब्याज नहीं। केंद्रीय बैंक ने एफसीएनआर (बैंक) जमा, विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और विदेशी मुद्रा उधारी के बारे में 'अक्सर पूछे जाने वाले सवालों' (एफएक्व) की सूची जारी करते हुए यह जानकारी दी।

आरबीआई ने कहा कि बैंक एफसीएनआर (बी) खाताधारकों को ऋण दे सकते हैं और इन जमाओं को ऋण के बदले गिरवी भी रख सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को बिना



जोखिम के नए एफसीएनआर (बी) जमा जुटाने में मदद के लिए आठ जून को विशेष डॉलर-रुपया विदेशी मुद्रा अदला-बदली योजना शुरू की थी। इसका मकसद विदेशी पूंजी आकर्षित करना है। इस योजना के तहत बैंकों को तीन से पांच वर्ष की अवधि वाले एफसीएनआर (बी) जमा पर अधिक ब्याज दर देने की मंजूरी दी गई है।

आरबीआई ने कहा, रिजर्व बैंक प्राप्त जमा के लिए विदेशी मुद्रा अदला-बदली उपलब्ध कराएगा। यह एक साधारण खरीद/बिक्री विदेशी मुद्रा अदला-बदली है, जो केवल

मूल राशि को कवर करता है, ब्याज घटक नहीं।

एफएक्व के अनुसार, बैंक तीन वर्ष से कम अवधि के लिए भी मुद्रा अदला-बदली कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए न्यूनतम तीन वर्ष की मूल अवधि वाले नए पात्र एफसीएनआर (बी) जमा जुटाने अनिवार्य होंगे।

केंद्रीय बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तीन वर्ष या उससे अधिक औसत परिपक्वता वाले बाह्य वाणिज्यिक उधारी के लिए भी डॉलर-रुपया अदला-बदली सुविधा शुरू की है। इसकी अवधि उधारी की परिपक्वता या पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुरूप होगी, जिसकी अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी।

इसके अलावा, अधिकृत डीलर श्रेणी-1 बैंकों द्वारा जुटाए गए न्यूनतम तीन वर्ष की परिपक्वता वाले विदेशी मुद्रा उधार के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

ईडी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के ठिकानों की तलाशी ली

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को राजेश एक्सपोर्ट्स के ठिकानों की तलाशी ली। कंपनी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बाजार नियामक सेबी की जांच के दायरे में है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि बेंगलूर में मुख्यालय वाली इस कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कार्रवाई की गई है। सूत्रों ने बताया कि बेंगलूर और मुंबई में कंपनी से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के एक अंतर्गत आदेश के मुताबिक, 'राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड पर आरोप है कि उसने पांच वर्षों में अपने समेकित राजस्व को 15 लाख करोड़ रूप से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। कंपनी ने यह आय मुख्य रूप से अपनी विदेशी अनुबंधियों, विशेषकर स्विट्जरलैंड स्थित वैलकैम्बी एएस से दिखाई, जबकि उस अनुबंधी के वित्तीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट में राशि बहुत कम दिखाई गई थी।'

सेबी ने आदेश में कहा कि कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजेश मेहता पर अगले आदेश तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजेश एक्सपोर्ट्स की प्रतिभूति खरीदने, बेचने या उनमें लेन-देन करने को लेकर रोक रहेगी। राजेश एक्सपोर्ट्स ने किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि उसके द्वारा उल्लेखित आय सही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार नियामक और कंपनी के बीच संवाद में कोई कमी रह गई थी।

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी की खाई में धक्का देकर की गई थी हत्या, मंगेतर सहित दो गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुणे/भाषा। महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन विशाल अग्रवाल की सुनियोजित तरीके से खाई में धक्का देकर हत्या की गई थी और उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने मंगलवार को यह सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मामले में केतन की मंगेतर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 18 जून की है। शुरुआत में इसे लोहागढ़ किले से पैर फिसलने के कारण हुई दुर्घटना माना जा रहा था लेकिन

गहन जांच में यह सुनियोजित हत्या की साजिश निकली। पुलिस ने बताया कि केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल का जन्मदिन मनाते के लिए 18 जून को लोहागढ़ ट्रेकिंग पर गए थे। दोनों की शादी नवंबर में होने वाली थी।

खबरों के मुताबिक, परिवारों ने शादी के लिए राजस्थान में एक महल को 17 करोड़ रूप में बुक किया था और मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए दो निजी विमानों की व्यवस्था की गई थी। सिया ने शुरुआत में पुलिस को बताया कि तस्वीर खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। तीन घंटे चले बचाव अभियान के बाद बचाव दल ने उसका शव बाहर



निकाला। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सिया और उसके प्रेमी केतन बाबूलाल चौधरी ने केतन को धक्का देकर उसकी हत्या कर दी और इसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि शुरु में इसे दुर्घटना का मामला माना जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि पुणे जिले के गहुंजे निवासी और परिवार के

रियल एस्टेट कारोबार के निदेशक केतन अग्रवाल, किले पर तेज हवाओं के बीच फोटो खींचते समय लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। लोनावला ग्रामीण पुलिस ने सिया के बयान के आधार पर दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। सिया ने पुलिस को बताया था कि पहाड़ी पर स्थित किले में घूमने के दौरान केतन फिसलकर गिर गये थे। पुणे ग्रामीण के पुलिस

अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि मौत की परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। उन्होंने कहा, हमारी टीम ने वित्तीय विवादों और व्यक्तिगत संबंधों समेत विभिन्न पहलुओं से जांच की। इसी दौरान पता चला कि सिया गोयल का पुणे के कोडवा निवासी चेतन बाबूलाल चौधरी (22) के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि सिया गोयल केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने तथा केतन के रिश्ते में बाधा मानती थी। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि सिया के तहत सिया घूमने के

बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ले गई। बाद में केतन को भी वहां बुलाया गया और दोनों ने मिलकर कथित तौर पर केतन को खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। संदेह के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा ने सबसे पहले केतन चौधरी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने कथित रूप से स्वीकार किया कि केतन उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसने और सिया ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि केतन से मिली जानकारी के आधार पर सिया गोयल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि विशाल अग्रवाल की पिता एक महत्वपूर्ण दुर्ग है।

के आधार पर लोनावला ग्रामीण पुलिस ने मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत हत्या और अपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा, 'जब पुलिस मेरे बेटे का शव लेकर आई, तो सिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था।' पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना से जुड़ी सभी कड़ियों को जोड़ने, फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने और इस साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की संभावित भूमिका की जांच के लिए पड़ताल जारी है। लोहागढ़ किला मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दुर्ग है।



वीओसी बंदरगाह ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी की : रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चेन्नई। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शामिल वीओसी बंदरगाह ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से अपने कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध रूप से 45 प्रतिशत की कमी दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोनोवाल ने बंदरगाह की पहली 'सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट' जारी करते हुए कहा, कार्बन उत्सर्जन को 45 प्रतिशत तक कम करने के प्रयासों को प्रमाणित करता है और भारत के अग्रणी हरित बंदरगाहों में से एक के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करता है।

बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने कई टिकाऊ पहल की भी शुरुआत की। इनमें वडोदरा के गति शक्ति विश्वविद्यालय और वीओसी बंदरगाह के साथ समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर करना और हाल ही में बने केंद्रीय विद्यालय वीओसी बंदरगाह प्राधिकरण में 2026-27 के लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम की भी शुरुआत भी शामिल है।

मोदी के प्रधानमंत्री बनने की वजह से ही मैं केंद्रीय मंत्री बन सका: जॉर्ज कुरियन



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय राज्य मंत्री पद से अपना इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद कहा कि वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद में स्थान पा सके। कुरियन ने मंगलवार को फेसबुक पर साझा किए गए एक भावुक संदेश में कहा कि केंद्रीय मंत्री बनना उनके लिए ऐसा अवसर था, जिसकी उन्होंने 'सपने में भी कल्पना नहीं की थी'। अपने विदाई संदेश में उन्होंने मंत्री पद तक पहुंचने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को प्रमुखता से रेखांकित करते हुए कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि राष्ट्रपति

लखनऊ अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो : थरु

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरु ने लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत पर मंगलवार को दुःख जताया और कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों तथा नियमों का सख्ती से पालन किए जाने की आवश्यकता है। जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष ने समिति के चार दिवसीय अध्ययन दौरे के दूसरे चरण के तहत श्रीनगर रवाना होने से पहले यहां संवाददाताओं से कहा, 'जिन परिवारों ने अपने प्रियजन को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। इससे पहले दिल्ली में भी इसी तरह की घटना हुई थी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा मानकों और संबंधित नियमों का उचित ढंग से पालन हो, ताकि भविष्य में ऐसी



घटनाएं न हों।' समिति के जम्मू दौरे के बारे में उन्होंने कहा कि पूरा दौरा समाप्त होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। थरु ने कहा, 'अब हम श्रीनगर जा रहे हैं, जहां हम उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अगले दिन कारगिल जाएंगे और फिर लेह का दौरा करेंगे। पूरे दौरे के समापन के बाद हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।' कांग्रेस नेता का कहना था कि समिति केंद्रशासित प्रदेश में तीन विशिष्ट विषयों के अध्ययन के लिए आई है। इनमें भारत-पाकिस्तान संबंध, भारत-चीन संबंध तथा पासपोर्ट कार्यालयों और पासपोर्ट सेवा केंद्रों के कामकाज का अध्ययन शामिल है।

तमिलनाडु विधानसभा में भ्रष्टाचार के आरोपों पर हंगामा, द्रमुक सदस्यों का वाकआउट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को विधानसभा में विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कणम (द्रमुक) पर तीखा हमला करते हुए उसके पूर्ववर्ती शासनकाल में कथित भ्रष्टाचार को 'पार्टी फंड' के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी बताया। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर द्रमुक सदस्यों ने सदन में विरोध जताया और बाद में वाकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले द्रमुक सरकार ने विभिन्न विभागों के सरकारी धन को 'पार्टी फंड' के लिए इस्तेमाल किया था।

मुख्यमंत्री के जवाब को रोकने की कोशिश करते हुए उदयनिधि अपनी सीट से खड़े हो गए और विधानसभा अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर से हस्तक्षेप कर मुख्यमंत्री से आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने की मांग की। हालांकि अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि राज्यापाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री को अपना जवाब पूरा करने दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद द्रमुक सदस्यों का विरोध जारी रहा। इसके बाद विजय ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा कि तमिलनाडु वेनी कषम (टीवीके) कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगी और न ही किसी को सरकारी खजाने की 'लूट' करने देगी। शोर-शराबे के बीच मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रमक रुख अपनाते हुए कहा कि उनकी सरकार पार्टी फंड संग्रह' के नाम पर कथित रूप से गबन किए गए सार्वजनिक धन की वसूली करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार



मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में स्टालिन जैसा इशारा किया, द्रमुक पर तीखा हमला बोला

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन द्वारा पूर्व में किये गए एक इशारे को तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को दोहराया और विपक्षी द्रविड़ मुनेत्र कणम (द्रमुक) पर तीखा हमला बोलेते हुए कहा कि शेतान को बुराई के बारे में नहीं बोलना चाहिए। करीब 45 मिनट के अपने भाषण के अंत में विजय ने विपक्ष की खाली सीटों अपना जवाब पूरा करने दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद द्रमुक सदस्यों का विरोध जारी रहा। इसके बाद विजय ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा कि तमिलनाडु वेनी कषम (टीवीके) कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगी और न ही किसी को सरकारी खजाने की 'लूट' करने देगी। शोर-शराबे के बीच मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रमक रुख अपनाते हुए कहा कि उनकी सरकार पार्टी फंड संग्रह' के नाम पर कथित रूप से गबन किए गए सार्वजनिक धन की वसूली करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार

करने) जैसा इशारा किया। सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेज थपथाकर जोरदार समर्थन किया और विधानसभा अध्यक्ष भी मुरकुराते नजर आए। विधानसभा चुनाव से पहले मार्च में, कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा समझौता होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री और द्रमुक प्रमुख एम. के. स्टालिन ने द्रमुक राज्य मुख्यालय अन्ना अरिवलयम' से निकलते की ओर संकेत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर से पूछा कि क्या वह सदन में हाथ से एक इशारा कर सकते हैं। विजय ने कहा, 'मैं यह इशारा द्रमुक सदस्यों की मौजूदगी में करना चाहता था, लेकिन वे सभी सदन से बहिर्गमन कर गए हैं। क्या आपकी अनुमति से मैं यह इशारा कर सकता हूँ?' इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत कहा, 'क्यों नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है।' इसके बाद, मुरकुराते हुए विजय ने हाथ से काटने (सफाया

कहा। उदयनिधि ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सत्तारूढ़ तमिलना वेनी कषम (टीवीके) पर निशाना साधते हुए कहा था, 'बुराई सामने चुप रहना भी एक तरह की बुराई है।' अपने भाषण में विजय ने द्रमुक नेतृत्व का मजाक उड़ाते हुए एक व्यंग्यात्मक कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बच्चे के पिता को ढूँढ रहा था। तभी एक लड़का उसके पास आया और पूछा, आप क्या ढूँढ रहे हैं?' बुजुर्ग ने जवाब दिया, मुझे बताया गया था कि तुम्हारे पिता यहीं होंगे, इसलिए मैं उन्हें ढूँढ रहा हूँ। वह कहाँ हैं? मुझे वह कहीं दिख नहीं रहे हैं।' द्रमुक के बहिर्गमन के बाद सदन में पार्टी के विधायकों की अनुपस्थिति, और विधानसभा चुनाव में हार के कारण उसके (द्रमुक के) सत्ता में वापस न आ पाने पर तंज करते हुए विजय ने कहा, 'हमें भी व्यंग्य करना आता है।'

लोगों को, चाहे वे द्रमुक शासनकाल से ही क्यों न जुड़े हों, कानून के दायरे में लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री की इन टिप्पणियों पर विपक्षी सदस्यों ने तीखी आपत्ति जताई। उदयनिधि ने अध्यक्ष से उन्हें सदन में जवाब देने का अवसर देने की मांग की। विजय ने इस दावे को खारिज किया कि उनकी सरकार 'द्रमुक की कृपा' से चल रही है। उन्होंने कहा कि वाम दलों ने स्वतंत्र रूप से टीवीके का समर्थन करने का निर्णय लिया था, जबकि कांग्रेस, वीसीके और आईएमएल को उनके समर्थन के बदले मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया।

उन्होंने कहा, 'हम द्रमुक की कृपा पर निर्भर नहीं हैं। हम उन लोगों की बदौलत सरकार चला रहे हैं जिन्होंने हमें चुना है।' इसके बाद उदयनिधि के नेतृत्व में द्रमुक सदस्य मुख्यमंत्री का भाषण पूरा होने से पहले ही सदन से बाहर चले गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की स्थिरता और जनता का भरोसा करते हुए विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि उनकी सरकार केवल बाहरी राजनीतिक समर्थन के सहारे चल रही है।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के आठ सदस्यों को मंत्री बनाया है। उन्होंने इसे डॉ. भीमराव आंबेडकर की समान प्रतिनिधित्व की परिष्करण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। बाद में विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उदयनिधि स्टालिन ने सदन की कार्यवाही की आलोचना की और कथित प्रक्रियागत उल्लंघनों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'यदि मुख्यमंत्री के पास किसी अनियमितता के वास्तविक सबूत हैं तो उन्हें निराधार आरोप लगाने के बजाय औपचारिक रूप से सदन के पटल पर रखना चाहिए।'



तमिलनाडु सरकार थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की अनुमति संबंधी आदेश के खिलाफ न्यायालय पहुंची

नई दिल्ली/चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें राज्य में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की अनुमति दी गई थी। सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार के वकील बी. करुणाकरन के माध्यम से 11 जून को यह याचिका दाखिल की। वकील ने पुष्टि की कि यह याचिका मद्रास उच्च न्यायालय की मद्रुं पीठ के छह जनवरी के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें एकल न्यायाधीश के एक दिसंबर 2025 के फैसले को बरकरार रखा गया था। उस आदेश में कहा गया था कि त्योहार के दिन पारंपरिक रूप से दीप जलाया जाएगा।

उच्च न्यायालय ने छह जनवरी के अपने आदेश में कहा था कि इस धार्मिक प्रथा को लेकर कानून-व्यवस्था की जो आशंका जताई जा रही है, वह केवल एक 'काल्पनिक डर' है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि जिस स्थान पर पत्थर का स्तंभ (दीपस्तंभ/दीपथुण्णु) स्थित है, वह श्री सुब्रह्मण्य स्वामी मंदिर की संपत्ति है और वर्तमान में वक्फ बोर्ड का इस मामले में कोई अधिकार नहीं बनता। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था, यह मानना मुश्किल और हास्यास्पद है कि अपने क्षेत्राधिकार में स्थित मंदिर की भूमि पर वर्ष में एक विशेष दिन मंदिर प्रतिनिधियों द्वारा दीप जलाने से सार्वजनिक शांति भंग जाएगी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में का कि ऐसा केवल तभी हो सकता है जब ऐसी अशांति स्थिति उत्पन्न हो सके। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी राज्य राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस स्तर तक नहीं गिरे। यह मामला राम रविकुमार और अन्य की याचिका से जुड़ा है, जिसमें हर साल कार्तिकाश्वी दीपम उत्सव के दौरान थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी स्थित प्राचीन पत्थर स्तंभ पर पवित्र दीप जलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। एक दिसंबर 2025 को एकल न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार करते हुए त्योहार के दिन दीप जलाने का आदेश दिया था। हालांकि, तत्कालीन द्रमुक सरकार, मंदिर प्रबंधन और थिरुपरनकुंद्रम स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बहुशा औलिया दरगाह ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। राज्य सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा था कि पहाड़ी के शिखर पर, जो दरगाह के पास स्थित है, दीप जलाने से सांभ्रायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि वक्फ बोर्ड का इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से यह दावा किया गया था कि दीपस्तंभ दरगाह का है, जिसे अदालत ने 'भ्रामक और अनुचित' टिप्पणी बताया।

प्रतिनिधियों द्वारा दीप जलाने से सार्वजनिक शांति भंग जाएगी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में का कि ऐसा केवल तभी हो सकता है जब ऐसी अशांति स्थिति उत्पन्न हो सके। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी राज्य राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस स्तर तक नहीं गिरे। यह मामला राम रविकुमार और अन्य की याचिका से जुड़ा है, जिसमें हर साल कार्तिकाश्वी दीपम उत्सव के दौरान थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी स्थित प्राचीन पत्थर स्तंभ पर पवित्र दीप जलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। एक दिसंबर 2025 को एकल न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार करते हुए त्योहार के दिन दीप जलाने का आदेश दिया था। हालांकि, तत्कालीन द्रमुक सरकार, मंदिर प्रबंधन और थिरुपरनकुंद्रम स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बहुशा औलिया दरगाह ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। राज्य सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा था कि पहाड़ी के शिखर पर, जो दरगाह के पास स्थित है, दीप जलाने से सांभ्रायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि वक्फ बोर्ड का इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से यह दावा किया गया था कि दीपस्तंभ दरगाह का है, जिसे अदालत ने 'भ्रामक और अनुचित' टिप्पणी बताया।

'हम सब आपके साथ हैं': विजय के लिए जन्मदिन पर कीर्ति सुरेश का संदेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व और जनसेवा के नए अध्याय की सराहना की है। तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वह सोमवार को 52 वर्ष के हो गए। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने सोमवार रात सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि पहले उनके जन्मदिन पर प्रशंसक उनकी फिल्मों से जुड़ी घोषणाओं, उनके फस्ट लुक, टीजर और ट्रेलर का इंतजार करते थे। कीर्ति सुरेश ने विजय के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, सालों तक आपका जन्मदिन एक नयी फिल्म के



फस्ट लुक, टीजर या ट्रेलर का इंतजार लेकर आता था। यह एक परंपरा बन गई थी जिसका हम सभी इंतजार करते थे। उन्होंने कहा, पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया के सामने कोई नया किरदार नहीं आ रहा है। इसके बजाय हम कुछ और अधिक महत्वपूर्ण

देख रहे हैं—आप खुद को फिर से पेश कर रहे हैं, इस बार पर्दे के हीरो के रूप में नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी के नए अध्याय में कदम रखने वाले नेता के रूप में। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने 2017 की फिल्म 'बैरवा' और 2018 की 'सरकार' में विजय के साथ काम किया है। अभिनेत्री ने विजय के नए राजनीतिक कदम को एक नई शुरुआत बताते हुए समर्थन जताया। उन्होंने लिखा, 'हम सब आपके साथ हैं।' अपने संदेश के अंत में कीर्ति सुरेश ने लिखा, हमेशा हमारे दिलों में खास जगह रखने वाले थलपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं। विजय ने 2024 में अपनी पार्टी तमिलना वेनी कषम (टीवीके) की शुरुआत कर राजनीति में प्रवेश किया था। हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस सहित अन्य दलों के समर्थन से उसने सरकार बनाई।

कतर में जान गंवाने वाले तीन युवकों के शव लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं : विजय

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कतर में एक औद्योगिक इकाई में आग लगने की घटना में राज्य के तीन युवकों की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक शोक संतप्त परिवार को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की मंगलवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि राज्य सरकार मृतकों के शवों को लाने के लिए त्वरित कदम उठा रही है। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा, 'कतर में कारखाने में आग लगने से पश्चित, सजितकुमार और सुविन की मृत्यु की दुखद खबर सुनकर मैं

अत्यंत दुखी हूँ।' उन्होंने कहा कि मृतकों के शवों को जल्द से जल्द तमिलनाडु लाने के लिए विदेश मंत्रालय और कतर में भारतीय दूतावास के साथ समन्वय के साथ सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अनिवार्य तमिल कल्याण मंत्री के. तेनारासु को निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया में तेजी लाएं और संबंधित अधिकारियों के साथ निकट समन्वय बनाए रखें। विजय ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सार्वजनिक राहत कोष से 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के तिरुवेलूर जिले में एक निजी समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात इकाई (सीफूड प्रोसेसिंग) और एक्सपोर्ट यूनिट) में हुए अमोनिया गैस रिसाव के कारण जान गंवाने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर नौ हो गई। सरकार ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी

विज्ञापित में बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वालों में सभी महिलाएं हैं। इनमें से सात महिलाएं ओडिशा की और दो असम की रहने वाली थीं। विज्ञापित के अनुसार, मृत महिलाओं में से आठ की पहचान शिबानी, जुमानी जुआंगा, गीता जुआंगा, पूर्णिमा जुआंगा, चंपावती जुआंगा, प्रभावती जुआंगा, सीता हसदा और अंजिता सोरने के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है। यह औद्योगिक रासायनिक

रिसाव 21 जून को पेरियापालयम के पास कनिगोपेर/संजुगरानाई इलाके में स्थित इकाई में नियमित औद्योगिक गतिविधियों के दौरान हुआ था। अस्पतालों में भर्ती कुल 69 लोगों में से 27 लोगों का इलाज वेल्स अस्पताल में, 18 का वेंकटेश्वर अस्पताल में, 11 का राजगंधी सरकारी सामान्य अस्पताल में और 13 का इलाज यहां स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। दो अन्य लोगों को पहले ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हादसे से

प्रभावित लोगों को सांस लेने के जरिए अमोनिया गैस अंदर जाने के गंभीर लक्षणों के बाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। इन लक्षणों में सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ, खांसी, छाती में बेचैनी, आंखों और धंसन नली में जलन शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती लोगों के स्वास्थ्य की कड़ी निगरानी की जा रही है।

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई-निविदा सूचना
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मुख्य कारखाना प्रबंधक, केंद्रिय एवं वैधानिक कारखाना, उ.प.रे. बीकानेर द्वारा खुली ई-निविदा सूचना संख्या 07R-MECH-BKNW-BOXNH-26 निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य का नाम: ई. एवं वी. कारखाना, उ.प. रेलवे, बीकानेर में स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार बॉक्सएंगेजमेंट (BOXNH) कार्य। कार्य की अनुमानित लागत: ₹. 3,74,61,294.00 (तीस लाख सहस्र)। बयाना पत्रिका सं. 7,49,200.00। ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं खुलने का समय व दिनांक: 14.07.2026 को 14:30 बजे तक। ई-निविदा यूपी डिन 15:00 बजे खोली जाएगी। वेबसाइट विवरण जहाँ से ई-निविदा की पूर्ण जानकारी देखी जा सकती है: www.teps.gov.in 905-MG/26

प्रत्यक्ष साक्षात्कार WALK-IN-INTERVIEW
आईएमएअर (IMR) परियोजनाओं के अंतिम योग थिरुक्क (Yoga Therapist) एवं जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) के पदों के लिए संविदा (Contractual) आधार पर बॉक-इन्टरव्यू उपरोक्त पते पर स्थित कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में पहले लिखित परीक्षा (Written Test) होगी, जिसके बाद चयन समिति के बोर्ड द्वारा साक्षात्कार (Interview) आयोजित किया जाएगा। Walk-in-Interview for the posts of Yoga Therapist and Junior Research Fellow (JRF) under IMR Projects, on a contractual basis will be held at the office of above address. The selection procedure will comprise a Written Test followed by an Interview conducted by a Board of the Selection Committee.

Name & No. of Vacancy	Date/Time
Yoga Therapist- 02 No (CSMCARI - 01 & ALRARI - 01)	09.07.2026/ 11 AM
JRF- 01 No	10.07.2026/ 11 AM

For application form, details of Educational Qualification, Experience, Remuneration and other details visit: www.ctsrw.rail.in

हस्ताक्षरित/-
सहायक निदेशक (प्रभारी)

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

प्रयागराज में खान ग्लोबल स्टीज समेत चार कोचिंग संस्थान सील

प्रयागराज/भाषा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत के बाद प्रयागराज में मानकों का पालन नहीं करने के लिए खान ग्लोबल स्टीज समेत चार कोचिंग संस्थानों को मंगलवार को सील कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के एक अधिकारी ने बताया कि लखनऊ की घटना के मद्देनजर खान ग्लोबल स्टीज समेत चार कोचिंग संस्थानों को मानक पूरे नहीं करने के कारण सील किया गया। उन्होंने बताया कि खान ग्लोबल स्टीज को मानकों का पालन नहीं करने के कारण सील किया गया। इसके अलावा 'सुपर क्लाइमेक्स', 'टारगेट ऑन' और एक अन्य कोचिंग संस्थान के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। अधिकारी ने बताया कि मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए करीब 50 कोचिंग संस्थानों को कार्रवाई के लिए धित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों के मानचित्र सामुदायिक सुविधाओं की उपयोग के तहत स्वीकृत नहीं हैं और इनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।



विकसित बिहार का मंत्र शहरीकरण, औद्योगीकरण और पर्यटन : नीतीश मिश्रा

पटना/भाषा। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि विकसित बिहार के लिए शहरीकरण, औद्योगीकरण और पर्यटन तीन प्रमुख आधार हैं तथा राज्य इन क्षेत्रों के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मिश्रा ने पटना स्थित अधिेशन भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग और विश्व बैंक की ओर से आयोजित दो दिवसीय 'बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम' का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार ने पिछले 20 वर्षों में विकास की लंबी और सकारात्मक यात्रा तय की है। उन्होंने कहा, अब समय बदल गया है। हमें ऐसे शहर विकसित करने होंगे जो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों और जहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। मंत्री ने बताया कि शहरी कायाकल्प के लिए विश्व बैंक और विभाग के बीच साझेदारी हुई है, जिसके तहत विश्व बैंक आगे 10 वर्षों तक नगर रथानीय निकायों (ग्रामीण) की वित्तीय आत्मनिर्भरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेगा।

गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह को आव्रजन चौकी घोषित किया

नई दिल्ली/भाषा। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल स्थित हल्दिया समुद्री बंदरगाह को आव्रजन चौकी घोषित किया है। सोमवार को जारी गजट अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। इसके साथ ही यह देश का 4 वां ऐसा समुद्री बंदरगाह बन गया है, जहां आव्रजन संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी। पिछले वर्ष सितंबर में केंद्र सरकार ने 34 समुद्री और नदी बंदरगाहों को आव्रजन बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया था। गृह मंत्रालय ने यह आदेश आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम 2025 (अधिनियम संख्या 13, 2025) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया है।

अवैध प्रवासी निर्वासित किए जा रहे, वास्तविक भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं : शुभेदु अधिकारी



कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने हजारों अवैध प्रवासियों की पहचान की है और उन्हें वापस भेजना शुरू कर दिया है। अधिकारी ने वास्तविक भारतीय नागरिकों को भरोसा दिलाया कि उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 10,000 अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें सीमा के पार भेजा जा चुका है, जबकि 1,800 अन्य लोग 12 केंद्रों में वापस भेजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "भारत के वास्तविक नागरिकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म या समुदाय से हैं या उनकी राजनीतिक संबद्धता क्या है।"

युगल के बाद एकल मे भी वापसी करेंगी सेरेना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लंदन/एपी। युगल में वापसी करने के बाद अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स अब एकल में भी वापसी करने के लिए तैयार हैं। सेरेना प्रतिष्ठित विंबलडन टूर्नामेंट के साथ एकल प्रारूप में वापसी करेंगी। ऑल इंग्लैंड क्लब ने उन्हें महिला एकल स्पर्धा के लिए वाइल्ड कार्ड दिया है। यह 44 वर्षीय खिलाड़ी सोमवार से शुरू हो रहे शासक टूर्नामेंट के लिए जब उत्तरी तो सभी की नजर उन पर टिकी होगी।

ईस्ट कोस्ट रेलवे क्षेत्र में 'कवच' प्रणाली से यात्रियों की सुरक्षा बड़ेगी: माझी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को कहा कि ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) क्षेत्र के 631 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क पर 'कवच' प्रणाली की तैनाती से यात्रियों की सुरक्षा और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी भारतीय रेल द्वारा ईस्ट कोस्ट रेलवे क्षेत्र में सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए 270 करोड़ रुपये की लागत से 'कवच' प्रणाली लागू करने को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद की। माझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "स्वदेश में विकसित यह आधुनिक तकनीक संपर्क व्यवस्था को और मजबूत करेगी, आर्थिक विकास को गति देगी तथा ओडिशा के लोगों के लिए अधिक सुरक्षित और दक्ष रेल प्रणाली के निर्माण में योगदान

देगी।" उन्होंने इस पहल को राज्य के रेल बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है, कहा कि इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा, ट्रेन परिचालन में सुधार होगा और रेल सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री

अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। 'कवच' भारत में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है, जिसे सिग्नल की अवहेलना, अत्यधिक गति और ट्रेन टकराव जैसी घटनाओं को रोककर रेल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रणाली ट्रेनों की आवाजाही पर लगातार नजर रखती है और आवश्यकता पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगाकर परिचालन सुरक्षा को बढ़ाती है। यह परियोजना ईस्ट कोस्ट रेलवे के छह महत्वपूर्ण रेलखंडों—आपाल-बूढ़ापक, हरिदासपुर-पारादीप, खुर्दा रोड-बलांगीर, नौपाड़ा-गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ तथा बोखिली-सालुर्को कवर करेगी।

अधिकारी ने कहा कि 'कवच' प्रणाली घने कोहरे सहित प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में भी ट्रेनों के सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन में मदद करेगी, जिससे रेल सेवाओं की समयबद्धता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

पहाड़ी इलाकों में अति. सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही : मणिपुर के गृह मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



इंफाल/भाषा। मणिपुर के गृह मंत्री गोविंददास कोंथोंजम ने मंगलवार को कहा कि राज्य के पहाड़ी जिलों में अशांति से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा यूनिट भी शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्य में अशांति को जमा कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

कोंथोंजम ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घाटी क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अपेक्षाकृत शांत है, जिससे सुरक्षा बल पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, "घाटी क्षेत्रों में छोटी-मोटी घटनाएं हो सकती हैं, हालांकि पहाड़ी इलाकों में अशांति बनी हुई है। हमें घाटी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सुरक्षा बल पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकें।" मणिपुर

के पहाड़ी क्षेत्र राज्य के लगभग 90 प्रतिशत भौगोलिक हिस्से में फैले हुए हैं और हाल के महीनों में यहां आदिवासी समुदायों के विरोधी सशस्त्र समूहों के बीच तनाव बढ़ा है। मंत्री ने कहा, "अपराधियों को पकड़ने के लिए पहाड़ी इलाकों में और सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं, जिनमें सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट भी शामिल है, क्योंकि घाटी वाले इलाकों में अब कम गड़बड़ी है। हथियार जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।"

हथियार लूटने के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा 'अरामबाई टेंगगोल' के तीन कथित सदस्यों की हालिया गिरफ्तारी पर कोंथोंजम ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से चर्चा की है। हालांकि, मंत्री ने कहा कि खुफिया जानकारी से पता चला है कि घाटी के इलाकों में अभी भी अवैध हथियार मौजूद हैं। उन्होंने कहा, "हम अपील करते हैं कि उन हथियारों को सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाए ताकि एनआईए, सीबीआई या राज्य पुलिस को और गिरफ्तारियां न करनी पड़ें।"

मणिपुर के खिलाड़ियों के बिना अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में कोई भी भारतीय दल पूरा नहीं : मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह



इंफाल/भाषा। मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने मंगलवार को कहा कि बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में राज्य के खिलाड़ियों के बिना कोई भी भारतीय दल पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि मणिपुर ने अपने खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों से लगातार देश का नाम रोशन किया है। सिंह ने कहा कि भारतीय खेलों में मणिपुर के महत्वपूर्ण योगदान के मद्देनजर देश का पहला राष्ट्रीय खेल दिवस राज्य में स्थापित करने का फैसला किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय बन्कर दूरा होने के हैं और उन्होंने हाल ही में परिसर का निरीक्षण किया था।

सिंह ने ताम्रकांडे खिलाड़ी के तौर पर अपने अनुभव के बारे में कहा कि एशियाई खेल व ओलंपिक खेलों जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतना और देश का प्रतिनिधित्व करना महत्वपूर्ण है लेकिन खेल से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख अनुशासन है।

यह बयान कांग्रेस के कड़े विरोध के बीच आया है। कांग्रेस ने इस परियोजना को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि इससे पर्यावरण संतुलन पर असर पड़ेगा और इससे "एक व्यवसायी" को फायदा होगा। मीडियाकर्मियों से बातचीत में, बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने कहा, "हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हम इसे जरूर करेंगे।" सोनोवाल उस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार ग्रेट निकोबार परियोजना को आगे

ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा पांच जुलाई तक के लिए स्थगित

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (ओटेट) को पांच जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला दो परीक्षाओं की तारीखों के एक ही होने के विरोध में कुछ उम्मीदवारों द्वारा प्रदर्शन किये जाने के बाद लिया गया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई) ने पूर्व में ओटेट की परीक्षा 28 जून को आयोजित करने की घोषणा की थी।

अधिकारियों ने बताया कि उसी दिन विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग (ओएसएसएससी) ने भी परीक्षा आयोजित की है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की चिंताओं पर संज्ञान लेते हुए बीएसई ने ओटेट की परीक्षा अब पांच जुलाई को कराने का फैसला किया है।

अधिकारियों ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के तहत ओटेट दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली में पूर्वाह्न नौ बजे से 11.30 बजे तक (प्रथम प्रश्नपत्र) और दूसरी पाली में अपराह्न दो बजे से शाम 4.30 बजे तक (द्वितीय प्रश्नपत्र) परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि ओएसएसएससी परीक्षा मूल रूप से 20 जून को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे 28 जून तक के लिए टाल दिया गया था।

बिहार: सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को बताया 'खलनायक', राजद का हमला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा लालू प्रसाद को "सबसे बड़ा खलनायक" बताया जाने पर विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चौधरी ने एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती किए जाने के मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए कहा था, "सबसे बड़ा खलनायक, जिससे सभी डरते हैं, अब खुद डर में जी रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार में अब सुशासन की सरकार है।"

राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में चौधरी को "लालू जी की पाठशाला का उत्पाद" बताते हुए कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद वह "बिना जनादेश वाले मुख्यमंत्री" बन गए हैं। झा ने कहा, "हम सार्वजनिक भाषणों में भाषा की मर्यादा बनाए रखते हैं। हम खलनायकों को भी खलनायक नहीं कहते और यहां इस

धरती के सबसे बड़े 'नायक' को 'खलनायक' कहा जा रहा है।" उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी लालू प्रसाद की उसी "पाठशाला" के छात्र हैं लेकिन उन्होंने यहां की शिक्षा को आत्मसात नहीं किया और अब पूरी तरह अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दल का हिस्सा बन गए हैं। राजद की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने मुख्यमंत्री के बयान को "अनावश्यक और अपरिपक्व" बताया। उन्होंने कहा, "लालू प्रसाद को एक ऐसे संघर्षशील नेता के रूप में देखते हैं, जिन्होंने सशक्तिकरण आधारित कल्याणकारी राजनीति के बल पर लोगों के दिलों में जगह बनाई है।" मंडल ने दावा किया कि इस प्रकार की टिप्पणी से पिछड़े वर्गों के लोग आहत होंगे। उन्होंने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती किए जाने के फैसले की भी आलोचना की।

सरकार की 2028 से ग्रेट निकोबार परियोजना पर काम शुरू करने की योजना : सोनोवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028 तक महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार परियोजना पर काम शुरू करना है और इसके लिए द्वीपों और उनके आसपास के इलाकों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के सभी उपाय किए जाएंगे।

यह बयान कांग्रेस के कड़े विरोध के बीच आया है। कांग्रेस ने इस परियोजना को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि इससे पर्यावरण संतुलन पर असर पड़ेगा और इससे "एक व्यवसायी" को फायदा होगा। मीडियाकर्मियों से बातचीत में, बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने कहा, "हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हम इसे जरूर करेंगे।" सोनोवाल उस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार ग्रेट निकोबार परियोजना को आगे

बढ़ाएगी, जबकि इसे लेकर काफी राजनीतिक विरोध हो रहा है।

जब परियोजना की समय-सीमा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसे चरणों में बनाया जाएगा और पहला चरण वर्ष 2028 में शुरू होगा। ग्रेट निकोबार परियोजना का मकसद ग्रेट निकोबार को एक रणनीतिक समुद्री और आर्थिक केंद्र में बदलना है। इसके लिए ईस्ट-वेस्ट शिपिंग रूट से इसकी निकटता (लगभग 40 नौटिकल मील) का फायदा उठाया जाएगा और विदेशी पारगमन बंदरगाहों पर निर्भरता कम की जाएगी, साथ ही रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

भवानी देवी ने माफी मांगी, निलंबन पर फिर से विचार करने की अपील

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



नई दिल्ली/भाषा। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में टीम स्पर्धा के दौरान अपने व्यवहार के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए भारत की प्रमुख तलवारबाज भवानी देवी ने उन पर लगाए गए दो महीने के निलंबन पर फिर से विचार करने की अपील की है। इस घटना के बाद भवानी को 'काला कर्त' दिखाया गया था जिसके कारण अनुशासनात्मक नियमों के तहत उन्हें दो महीने के

निलंबन पर फिर से विचार करने और उसे कम करने या हटाने के लिए विश्व संस्था (एफआईए) को अनुरोध भेजा गया है। "अपील में भवानी के अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान बेहतरीन अनुशासनात्मक रिकॉर्ड का हवाला दिया है और बताया कि वह पहले कभी भी इस तरह की किसी घटना में शामिल नहीं रही हैं। एफआईए ने यह भी बताया कि आगले महीने विश्व चैंपियनशिप होने वाली है और लंबे समय तक निलंबित रहने से भारत के सबसे सफल तलवारबाजों से एक भवानी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगी।"

मेरी क्रिकेट किट खरीदने के लिये मां ने गहने बेच दिये थे : क्रांति गौड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



मैनचेस्टर/भाषा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नियमित सदस्य बनने के बावजूद तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ अपनी जड़ें और माता पिता के बलिवान नहीं भूली हैं और वह 210 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके उनके भरोसे पर खरी उतरना चाहती हैं।

मध्यप्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली गौड़ ने बताया कि एक क्रिकेट किट खरीदने के लिये उनकी मां ने अपने गहने बेच दिये थे। गौड़ ने जियोस्टार से कहा, "अगर आपका परिवार आपके साथ है तो दूसरे क्या कहते हैं, यह मायने नहीं रखता। ये बाहरी लोग आपकी मदद नहीं करते।

दिये थे। यह बहुत बड़ा बलिवान था। मेरा परिवार मेरे लिये काफी कुछ कर रहा था जिसने मुझे जिम्मेवारी का अहसास कराया। मैं उन्हें कुछ वापिस देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके हर बलिवान का फल मिले।"

क्रांति गौड़ ने कहा, "जिस समय कई लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी, मेरे परिवार ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। उन्होंने मेरे सपनों पर भरोसा किया।" उन्होंने कहा, "इससे मुझे लगातार अच्छा खेलने और लक्ष्य हासिल करने की ताकत मिली। जब परिवार आपके साथ होता है तो बाहरी दुनिया को अनदेखा करना आसान हो जाता है।" गौड़ की कामयाबी के बाद अब उनके गांव में क्रिकेट अकादमी खुल गई है और लड़कियां खेलों में कैरियर बना रही हैं।

सुविचार

मुस्कान एक ऐसा उपहार है जो बिना कुछ खर्च किए भी दूसरों को बहुत कुछ दे जाता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

लापरवाही की आग, जिंदगी खाक

फिर एक अग्रिकांड हो गया। इस बार लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक इमारत सुलग उठी, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। इस दुर्घटना के बाद कार्रवाई की घोषणाएं हो रही हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने आनन-फानन में उस 'अवैध व्यावसायिक इमारत' को गिराने का नोटिस भी जारी कर दिया। क्या इसके अधिकारियों को यह इमारत पहले दिखाई नहीं दे रही थी? अगर उन्होंने समय रहते कार्रवाई की होती तो यह अग्रिकांड ही न होता। हमारे देश में अधिकारी दुर्घटनाएं होने का इंतजार क्यों करते हैं? उनके द्वारा कर्तव्य में बरती जा रही यह लापरवाही जनता की जान पर भारी पड़ रही है। ऐसे अधिकारी इसलिए भी सुस्त रहते हैं, क्योंकि इन्हें कार्रवाई का डर नहीं रहता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? निलंबित कर दिए जाएंगे! उसके बाद चुपके से बहाल हो जाएंगे। जनता जान गंवाती है तो गंवाती रहे। ऐसे अधिकारियों का क्या जाता है? इनकी नोकरी चलती रहती है। इनके ऐशो-आराम में कोई कमी नहीं आती है। एलडीए ने इस रिहायशी इमारत को व्यावसायिक तौर पर गैर-कानूनी तरीके से चलाने के मामले में अपने ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। जनता का दुर्भाग्य है कि यहां जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए पहले अपनी जान देनी होती है। आश्चर्य की बात यह है कि इस तीन मंजिला इमारत को साल 2016 में गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन दो महीने से भी कम समय में उस आदेश को वापस ले लिया गया था।

जब दस साल पहले ही इमारत को गिराने का आदेश जारी हो गया था तो उसमें किसने हस्तक्षेप किया? जनता को यह जानने का हक है। अब एलडीए के ये शब्द पीड़ित परिवारों पर किसी वज्रपात से कम नहीं हैं, 'हमने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ... ऐसे अधिकारियों की पहचान करने और इतने सालों में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों का पता लगाने की प्रक्रिया चल रही है।' क्या एलडीए यह सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में ऐसा अग्रिकांड नहीं होगा? क्या अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि जो भी लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जाएगी? क्या वरिष्ठ अधिकारियों को यह नहीं मालूम कि सरकारी दफ्तरों में फाइलें कैसे रोकी जाती हैं, कैसे आगे बढ़ाई जाती हैं और उन्हें कैसे अंतिम मंजूरी दी जाती है? अधिकारियों की लापरवाही और सुस्ती से कहीं बड़ी समस्या सरकारी दफ्तरों में फैला भ्रष्टाचार है। बच्चा-बच्चा जानता है कि दफ्तरों में जायज काम के लिए रिश्तत मांगी जाती है। जो व्यक्ति रिश्तत नहीं देता, उस पर दबाव डाला जाता है। उससे रिश्तत लेने के लिए कई तरह के पैसे आजमाए जाते हैं। जब फाइल 'भारी' हो जाती है तो वह सरपट दौड़ती है। उसे हर जगह से मंजूरी मिल जाती है। जो पहले ही रिश्तत दे देता है, उसकी सारी गलतियां माफ होती हैं। उक्त मामले में कार्रवाई के तहत चार लोगों की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठता है- क्या इतने ही लोग दुर्घटना के जिम्मेदार हैं? क्या बाकी लोग अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभा रहे हैं? बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और एलडीए के कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है। कई टीमें जांच में जुटी हैं। जांच का दायरा इसी इमारत तक सीमित न रखें। उन सभी इमारतों की जांच करें, जिनके नियम विरुद्ध निर्माण और उपयोग का संदेह है। साथ ही, सभी इमारतों में मजबूत अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करें। आग लगने के बाद कार्रवाई करने से कहीं बेहतर है कि पहले ही उसे रोकने के इंतजार काम दें। इस काम में अधिकारियों की लापरवाही, सुस्ती और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न किया जाए।

ट्वीटर टॉक

किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के साथियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। उनके विचार, सुझाव और एनर्जी ही हमारे संगठन की असली पूंजी हैं। हम सब मिलकर एक मजबूत संगठन बनाएंगे।

-सचिन पायलट

देश की एकता और गौरव की रक्षा के लिए उनका त्याग और समर्पण भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। उनके विचार, आदर्श और 'राष्ट्र प्रथम' का संकल्प देशवासियों को मातृभूमि की सेवा करने और एक विकसित और मजबूत भारत बनाने के लिए लगातार प्रेरित करता रहेगा।

-अर्जुनराम मेघवाल

आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रख्यात राष्ट्रवादी विचारक और हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर हम उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी भावभंगी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

-दिया कुमारी

प्रेरक प्रसंग

वर्तमान पर विश्वास

एक वन-आश्रम में एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग दूर-दूर से उनके पास आशीर्वाद लेने आते, लेकिन वे न तो उपदेश देते थे और न ही लंबी बातें करते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला कि उसके पास सब कुछ है, महान और अवसरफिर भी उसके मन में हमेशा डर बना रहता है। साधु उसे बिना कुछ कहे जंगल में ले गए, जहां एक टूटा हुआ पुल पड़ा था। साधु ने उस पुल पर एक-एक लकड़ी रखनी शुरू की और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। युवक घबराकर बोला, 'यह खतरनाक है, हम गिर सकते हैं।' साधु मुस्कराए और बोले, 'डर इसलिए नहीं लाता क्योंकि पुल टूटा है, डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें अगले कदम पर विश्वास नहीं होता।' कुछ देर बाद वे सुरक्षित पार पहुंच गए। लोटते समय साधु ने कहा, 'जीवन भी इसी पुल की तरह है, पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखाता, लेकिन जो हर कदम ईमानदारी और विश्वास के साथ रखता है, उसके लिए रास्ता बनता चला जाता है।' उस दिन युवक समझ गया कि साहस भविष्य को पूरी तरह देखने से नहीं, बल्कि वर्तमान पर विश्वास करने से पैदा होता है।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor: Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act). Group Editor - Shreekrant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law. Regn No. RNI No.: TNHM / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वार्ताकार, डॉक्टर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबन्धता या धमकावट का व्यव करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उदासीन है कि गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पुरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकको पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत

हकीकत को स्वीकार करने में झिझक कैसी?

अवधेश कुमार

नोबाइल : 9811027208

सन 2014 के पहले भारत में आम धारणा यही थी कि देश में कांग्रेस के अलावा किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में कभी बहुमत प्राप्त नहीं हो सकता। कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य पार्टी के नेतृत्व में अगर कोई गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसका स्थिर होकर 5 वर्षों तक चलना मुश्किल होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सन 1999 से 2004 तक की पहली सरकार थी जिसका कार्यकाल पूरा होना निश्चित था। लोकसभा भंग कर समय पूर्व चुनाव कराने के कारण वह सरकार भी 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाया। इसके पहले 1996 में वाजपेयी सरकार केवल 13 दिन रही और 1998 में एक वर्ष। 1977 में पहले गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार ढाई वर्ष ही जीवित रह पाती तो 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार केवल 11 महीने चल सकी। संयुक्त मोर्चा की सरकारों में एचडी देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल जैसे दो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुल डेढ़ वर्ष ही सरकार चली। इसी बीच 1991 में नरसिंह राव के नेतृत्व में 232 सांसदों की अल्पमत कांग्रेस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2004 में कांग्रेस के पास केवल 145 सांसद थे लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने पहले 5 वर्ष और फिर 206 सांसदों के साथ अपना 5 वर्ष का काल पूरा किया। इस पृष्ठभूमि में विचार करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक समय तक पद पर बने रहने का रिकॉर्ड असाधारण प्रतीत होगा। दुखद है कि इस विषय के विरुद्ध अभियान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भाजपा के विरोधी समर्थक सभी विचार करें कि क्या 2014 के पूर्व कोई कल्पना कर सकता था कि भाजपा को संसद में बहुमत प्राप्त हो जाएगा?

यह दुखद है कि हमारे देश में पत्रकारों, एक्टिविस्टों, बुद्धिजीवियों, एनजीओ चलाने वालों के एक बड़े वर्ग में नरेंद्र मोदी, भाजपा, हिंदुत्व विचारधारा, संघ आदि को लेकर स्थायी घृणा का भाव है। कम से कम इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में उनके काम और संघ के भी विरुद्ध के व्यवहार को देखने के बाद इन्हें अपनी सोच और व्यवहार पर विचार करना चाहिए। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध इन लोगों ने क्यों ऐसा अभियान चलाया कि उन्हें इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर देखना ही स्वीकार करना सहज रूप में संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए किसी भी तर्क को ये अपने

आधारहीन तथ्यों और कुतर्कों से खारिज करने की कोशिश करते हैं। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा रिकॉर्ड बताना प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोटा दिखाने का अभियान कैसे हो गया? इसमें छोटे-बड़े की बात कैसे आ गई? यह बात ठीक है कि पंडित नेहरू के हाथों भारत का नेतृत्व 2 सितंबर, 1946 से लेकर उनकी 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु तक रही। किंतु स्वतंत्र भारत के संविधान के तहत पहले आम चुनाव के बाद बरकरार मताधिकार द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 13 मई, 1952 को ही पदभार ग्रहण किया था। इस तरह अपने निधन तक वे कुल 4397 दिन इस पद पर रहे। नरेंद्र मोदी 13 मई 2026 को 4398 दिन पूरी करके उससे आगे निकल गये। यह सच स्वीकार करने में क्या समस्या है?

कोशिश करेंगे और उसके लिए हर तरह के उपहास व निंदा पर उतर जाएंगे तो फिर ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। किसी को पंडित नेहरू के कार्यकाल, उनकी नीतियों, विचारों का समर्थन करने का अधिकार है तो दूसरे को उसकी आलोचना का। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भी लागू होती है। लेकिन मोदी के संदर्भ में आलोचना और निंदा समस्त मर्यादाओं और गरिमा को पार कर जाती है। हमेशा उन्हें छोटा दिखाने तो प्रतिक्रिया में फिर नेहरू जी से लेकर सारे कांग्रेसी नेताओं के भी उनके समर्थक ऐसी ही दुर्गतिक करेंगे। यह केवल भाजपा तक सीमित नहीं है। आप डिजिटल मीडिया या आम लोगों के बीच चले जाइए अमित लोग आपको नेहरू जी उनके परिवार को लेकर इस तरह की प्रतिक्रियाएं देते मिल जाएंगे। इसलिए अच्छा यह होता कि विरोधी

के रूप में विदेशी नेताओं के साथ उनके बेहतर संवाद हैं, अनेक नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं तथा सभी उनके बारे में सम्मानजनक भाषा क्यों करते हैं। उनके नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। सबसे बड़ी बात कि हिंदुत्व, भारत, भारतीयता, भारत की वैश्विक सोच, विश्व कल्याण के भाव आदि को उन्होंने विश्व मंच पर जिस तरीके से रखा है उससे न केवल भारत राष्ट्र के प्रति दुनिया की सोच बदल रही है बल्कि इसके प्रति आकर्षण और बढ़ा है। ठीक इसके विपरीत नेहरू जी और उनके संस्थानों में इस पूरी विचारधारा को लेकर जुगुप्सा का भाव रहा है और आज तक है। इसलिए देश में इसका विरोध होता है और विदेश में भी यहां से प्रभावित लॉबी ही ऐसा करती है। मोदी के शासनकाल में नेहरू जी के काल के विपरीत भारत तीव्र व सघन सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा और आज आम भारतीय को धीरे-धीरे समझ आने लगा है कि हम कौन हैं क्या हो गये थे और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। धीरे-धीरे हमारी संस्कृति, धर्म, परंपरा, अध्यात्म सबकी समझ विकसित हुई है और इसका परिणाम देश के सामूहिक व्यवहार के रूप दिखता है। आप देखेंगे कि विदेश में रहने वाले भारतवासियों में खितनी प्रख्यात भारतीयता, संस्कृति, धर्म, विरासत आदि को लेकर इन वर्षों में हुआ है वैसा पहले नहीं देखा गया। नेहरू जी और मोदी जी में यही मौलिक अंतर है। यह केवल वचन के स्तर पर नहीं है। सामाजिक न्याय को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के कारण आम लोगों की सक्षमता बढ़ी है। देश के युवक-युवतियों में स्वयं कुछ करने व महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास व आत्मसम्मान का भाव व्यावहारिक नीतियों के कारण बढ़ा है। यही कार्य स्वतंत्रता के बाद होना चाहिए जिसकी आकांक्षा स्वयं महात्मा गांधी से लेकर हमारे अनेक महापुरुषों की थी। ऐसा पहले होता भारत आंतरिक रूप से कुछ और होता एवं उसकी छवि तथा विश्व पर प्रभाव भी दूसरे रूप में होता। कश्मीर से लेकर मुख्य सुरक्षा मामलों पर नेहरू जी की नीति उनकी शिक्षा और सोच से प्रभावित थी। जम्मू कश्मीर, चीन आदि पर उसकी ट्रेजेडी हम आज तक भुगत रहे थे। मोदी की नीति ने इन मामलों पर टूटता, साहस और साधारण पराक्रम प्रदर्शित किया है। इससे भारत विरोधियों को भी व्यवहार पर पुनर्विचार करने को विवश होना पड़ा तथा भारत की विश्व स्तर पर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर एक दृढ़निश्चयी, सशक्त व निर्णायक कार्रवाई करने वाले की छवि बनी है। कोई इन बातों को न स्वीकारे तो उससे सच नहीं बदल जाता। बावजूद हम मानते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या पंडित नेहरू हम उनसे सहमत हो या असहमत हमारे अंदर सम्मान का भाव होना चाहिए।

नजरिया

मौत की फैक्ट्री बनते शहर और सोती हुई व्यवस्था

योगेश कुमार गोयल

नोबाइल : 9416740584.

लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोथिंग सेंटर में लगी आग में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत उस व्यवस्था के चेहरे से नकाब हटाने वाली त्रासदी है, जो वर्षों से भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के सहारे चल रही है। जिन बच्चों को उनके माता-पिता बेहतर भविष्य के सपने लेकर कोथिंग भेजते हैं, वे यदि धुएँ से भरे कमरों, बंद दरवाजों और अवैध निर्माणों के बीच दम तोड़ दें तो उसे केवल हादसा कहना सघाई से मुंह मोड़ना होगा। यह उन परिस्थितियों में हुई मौत है, जिसे रोका जा सकता था, टाला जा सकता था और जिसकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह वास्तव में हादसा था या फिर भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा किया गया एक सुनियोजित प्रशासनिक हत्याकांड? घटना के विवरण किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए पर्याप्त हैं। आग लगने के बाद छात्र जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे। कुछ तीसरी मंजिल से नीचे कूद गए, कुछ बाथरूम में छिपे गए, यह सोचकर कि शायद वहां धुएँ से बच सकेंगे लेकिन दम घुटने से उनकी मौत हो गई। यह दृश्य किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा का नहीं बल्कि उस इमारत का दृश्य था, जिसे नियमों की अनदेखी कर व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए तैयार किया गया था। जहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जहां फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं हुआ और जहां छात्रों की सुरक्षा से अधिक महत्व मुनाफे को दिया गया।

कुछ ही समय पहले दिल्ली के मालवीय नगर में भी भीषण आग ने 21 लोगों की जान ले ली थी। उससे पहले मुंडका, अनाज मंडी, करोल बाग, अलीपुर और उपहार सिलेना जैसे अनेक अग्रिकांड देश देख चुका है। हर बार जांच में लगभग एक जैसी बातें सामने आती हैं, अवैध निर्माण, बंद निकास मार्ग, फायर एनआरसी का अभाव, क्षमता से अधिक लोगों की मौजूदगी, प्रशासनिक अनदेखी और भ्रष्टाचार। यदि हर बार कारण एक जैसे हैं तो फिर इन घटनाओं को दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता का परिणाम माना जाना चाहिए। लखनऊ अग्रिकांड की प्रारंभिक जांच ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिस इमारत में कोथिंग सेंटर चल रहा था, वहां स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया था। सेटबैक क्षेत्र तक को कवर कर लिया गया था। नीचे पेट शॉप और गैरिंग जोन संचालित हो रहे



जब किसी भवन मालिक या अधिकारी की लापरवाही के कारण लोगों की मौत होती है तो उसे केवल प्रशासनिक गलती मानकर छोड़ देना न्याय के साथ खिलवाड़ है। ऐसे मामलों में कठोर आपराधिक दायित्व तय होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मानव जीवन की कीमत पर लाभ कमाने का साहस न कर सके।

थे जबकि ऊपर कोथिंग सेंटर और लाइब्रेरी चल रही थी। एक ही इमारत में अलग-अलग व्यावसायिक गतिविधियों का ऐसा मिश्रण सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक माना जाता है। सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया कि जिस रास्ते से छात्रों को बाहर निकलना था, वह प्रभावी रूप से बंद था। ऐसे में आग लगने के बाद उनके पास बचने का कोई विकल्प नहीं बचा। यह केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि मानव जीवन के प्रति घोर उपेक्षा का उदाहरण है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसी इमारतें अस्तित्व में आती कैसे हैं? क्या नगर निगम, विकास प्राधिकरण, फायर विभाग, विजली विभाग और स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होती? कोई भी अवैध निर्माण रातों-रात खड़ा नहीं हो जाता। उसकी नींव पड़ती है, दीवारें खड़ी होती हैं, मंजिलें बनती हैं, बिजली-पानी के कनेक्शन दिए

जाते हैं और फिर वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक विभाग शामिल होते हैं। सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार और मिलीभगत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि नियम केवल फाइलों में रह जाते हैं जबकि जमीन पर अवैधता का साम्राज्य खड़ा हो जाता है। देश का शहरी विकास मॉडल भी इस समस्या के लिए कम जिम्मेदार नहीं है।

आज अधिकांश शहरों में अधिक से अधिक लाभ कमाने की होड़ लगी हुई है। बिल्डर अतिरिक्त मंजिलें जोड़ देते हैं, सेटबैक क्षेत्र को कवर कर लेते हैं, बेसमेंट का उपयोग अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करते हैं और आपातकालीन निकास को स्टोर रूम में बदल देते हैं। बदले में कुछ अधिकारियों की जेबें गर्म हो जाती हैं और फाइलों में सब कुछ वैध दिखाई देने लगता है। नतीजा यह होता है कि एक पूरी इमारत धीरे-धीरे मौत के जाल

में बदल जाती है और किसी दिन एक विंगारी सैंकड़ों परिवारों की खुशियां छीन लेती है।

लखनऊ में बाथरूम में छिपे छात्रों की दम घुटने से हुई मौतें इस बात का प्रमाण हैं कि उन्हें बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं मिला। यदि पर्याप्त निकास द्वार होते, यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता, यदि नियमित निरीक्षण हुए होते और यदि संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई की होती तो संभव है कि ये सभी जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इन मौतों के पीछे केवल आग नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता, भ्रष्टाचार और जवाबदेही का अभाव भी जिम्मेदार है। अब समय केवल संवेदना व्यक्त करने का नहीं है। देश को एक कठोर और निर्णायक नीति की आवश्यकता है। सभी व्यावसायिक इमारतों, कोथिंग सेंटरों, अस्पतालों, होटलों और मॉल्स का नियमित तथा डिजिटल सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए। फायर एनओसी की पूरी प्रक्रिया अनलाइन और सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि कोई भी नागरिक किसी भवन की सुरक्षा स्थिति की जांच कर सके। अवैध निर्माण पर केवल जुर्माना लगाने की परंपरा समाप्त होनी चाहिए और ऐसे निर्माणों को तत्काल ध्वस्त किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिम्मेदारी केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिन अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में ऐसे अवैध निर्माण पनपते हैं, उन्हें भी समाप्त रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

कानूनी व्यवस्था में भी बदलाव की आवश्यकता है। जब किसी भवन मालिक या अधिकारी की लापरवाही के कारण लोगों की मौत होती है तो उसे केवल प्रशासनिक गलती मानकर छोड़ देना न्याय के साथ खिलवाड़ है। ऐसे मामलों में कठोर आपराधिक दायित्व तय होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मानव जीवन की कीमत पर लाभ कमाने का साहस न कर सके। लखनऊ का अग्रिकांड केवल 15 परिवारों का व्यक्तिगत दुःख नहीं है, यह पूरे समाज के लिए धैर्यमानी है। यह बताता है कि यदि हमारे व्यवस्था की खामियों को दूर नहीं किया, यदि भ्रष्टाचार और मिलीभगत पर अंकुश नहीं लगाया और यदि सुरक्षा मानकों को केवल कागजी औपचारिकता बनाए रखा तो अगली त्रासदी केवल समय का प्रश्न होगी। तब फिर कुछ मासूम जिंदगियां बुझ जाएंगी, कुछ परिवार हमेशा के लिए उजड़ जाएंगे और व्यवस्था फिर वही पुराना राग अलापेगी। इसलिए अब खोखले आश्वासनों का समय समाप्त हो चुका है। अब जरूरत है जवाबदेही, पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई की।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अमेरिका-ईरान करार के दीर्घकालिक समझौते का रूप लेने की उम्मीद : शरीफ

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ करार (एमओयू) बाद में 'दीर्घकालिक समझौते' का रूप ले लेगा।

अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व अन्य विवादित मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बृहस्पतिवार को इस्लामाबाद समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किए। शरीफ संसद को संबोधित कर रहे थे, जिसने चर्चा के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के विरोध के बावजूद 2026-27 का बजट पारित कर दिया।

शरीफ ने कहा, 'हमें पूरी

उम्मीद है कि अगले 60 दिन में यह एमओयू एक लंबे समय तक प्रभाव में रहने वाले समझौते में बदल जाएगा, जिससे दुनिया में शांति आएगी।'

इस्लामाबाद एमओयू के तहत स्विट्स रिजॉर्ट ऑफ बर्नस्टॉक में हुई हालिया उच्च-स्तरीय बातचीत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि गहन बातचीत रविवार को शुरू हुई और सोमवार को आधी रात के बाद तक चली, जिसमें अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों ने पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में जटिल मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगले 60 दिन में अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत होगी, जिसमें ईरान की परमाणु

संपत्तियों, बैलिस्टिक मिसाइलों और फ्रीज की गई संपत्तियों पर चर्चा की जाएगी।

शरीफ ने कहा, 'पाकिस्तान ने पूरी इमानदारी से दोनों पक्षों के बीच की दूरी को कम करने की हरसंभव कोशिश की।' उन्होंने कहा कि सोमवार तड़के मध्यस्थों द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया। शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका को 'महत्वपूर्ण' और 'ऐतिहासिक' बताते हुए इसके लिए संसद और देश को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेइशकियान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं।

सिंधु दर्शन



लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजदूतों, उद्यायुक्तों, आध्यात्मिक गुरुओं और श्रद्धालुओं के साथ मंगलवार को लेह में आयोजित 'सिंधु दर्शन महाकुंभ 2026' में हिस्सा लिया। इस दौरान दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे।

सिंदूर



त्रिपुरा के अगरतला जिले में मंगलवार को अंबुबाची उत्सव के दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों के तहत एक-दूसरे को कामाख्या सिंदूर लगाती महिलाएं।

वेतन असमानता पर पल्लवी जोशी का छलका दर्द, कहा- 'सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद मिली आधी फीस'

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री और प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने 80 और 90 के दशक में अपने अभिनय से घर-घर में पहचान बनाई। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक सफर तय किया। इस दौरान उन्हें वेतन असमानता का सामना करना पड़ा। इसको लेकर पल्लवी जोशी ने संग खुलकर अपनी बात रखी और दर्द बयां किया। पल्लवी जोशी ने कहा, 90 के दशक में, जब मैं अपने करियर के चरम पर थी, तब भी मुझे पुरुष कलाकारों की तुलना में कम वेतन मिलता था। उस समय में टीवी की सबसे ज्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं, लेकिन इसके बावजूद मेरे साथ काम करने वाले पुरुष कलाकारों की तुलना में मेरी कमाई काफी कम थी। पल्लवी जोशी ने बताया, एक समय ऐसा भी था जब एक मैगजीन कवर पेज पर मेरी और अभिनेता शंखर सुमन की तस्वीर एक साथ छपी थी। उस दौर में हम



दोनों टीवी के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा फीस पाने वाले कलाकारों में गिने जाते थे। शंखर सुमन को उस समय मेरी तुलना में लगभग दोगुनी फीस मिलती थी। उन्होंने कहा, यह किस्सा अपने आप में उस दौर की स्थिति को उजागर करता है कि कैसे महिला कलाकारों को बराबर काम और लोकप्रियता के बावजूद कम भुगतान किया जाता था। यह अंतर उस समय इंटरस्ट्री में सामान्य बात थी। उन्होंने कहा, भले ही मुझे उस

समय की सबसे सफल और ज्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्री माना जाता था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि पुरुष सहकलाकारों की तुलना में कमाई हमेशा कम ही रही। यह अनुभव मेरे लिए एक सोचने वाला विषय था और मैंने इसे उस समय चुपचाप स्वीकार किया, क्योंकि उस दौर में इस तरह के मुद्दों पर खुलकर बात नहीं होती थी। बता दें कि पल्लवी जोशी ने 80 और 90 के दशक में भारतीय टेलीविजन पर एक मजबूत पहचान बनाई थी। उन्होंने कई लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया, जिनमें 'मृगयानी', 'तलाश' और 'आरोहण' जैसे शो शामिल हैं। इस बातचीत के दौरान शंखर सुमन का भी जिक्र हुआ, जो उस समय टीवी इंडस्ट्री के बेहद लोकप्रिय अभिनेता थे। उन्होंने 'देख भाई देख', 'वाह जनाब' और 'मूवर्स एंड शेकरर्स' जैसे हिट शो से दर्शकों के बीच बड़ी पहचान बनाई थी और अभी यूट्यूब शो 'शंखर टुनाइट' को लेकर भी काफी चर्चा में हैं।

'अल्फा' के प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट ने एथलीट गुरिंदरवीर सिंह को गिफ्ट किया मोतीचूर लड्डू का डिब्बा

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म 'अल्फा' में अपनी एक्शन अवतार को लेकर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इसके ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया। फिलहाल, वह फिल्म के प्रमोशन में जुटी हैं। इस बीच उन्होंने भारत के सबसे तेज एथलीट बनने का फैसला कब लिया। इस पर गुरिंदरवीर ने अपने बचपन की यादें साझा कीं और कहा, बचपन में मैं अपने पिता की ट्रांकिंग और मेडल साफ किया करता था। उनकी एक फोटो भी थी, जिसमें वह जंप कर रहे हैं और वॉलीबॉल खेल रहे हैं। फिर मैंने उसी बॉल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा, जिसके बाद मैंने एथलीट बनने की ठान ली। उन्होंने कहा, लोगों ने मुझे बताया कि इस क्षेत्र में बहुत मेहनत लगती है और आसान नहीं है, लेकिन मैंने तय किया कि मैं इसके लिए कड़ी तैयारी करूंगा।

गुरिंदरवीर ने बताया, मेरे पिता पहले वॉलीबॉल खेलते थे, लेकिन एक चोट के कारण उन्हें खेल



छोड़ना पड़ा। वह अक्सर कहा करते थे 'अगर मैं खेलना जारी रखता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती।' पिता के इस अधूरे सपने को मैंने अपना सपना बना लिया। उन्होंने आगे बताया, जब मैंने अपनी पहला बड़ा रस पूरी की और पिता को फोन कर पूछा कि अब कैसा महसूस हो रहा है।

इस पर मेरे पिता ने खुशी जताई और कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इस बातचीत के दौरान आलिया भट्ट ने गुरिंदरवीर सिंह को 'मोतीचूर लड्डू' का एक डिब्बा गिफ्ट किया। इस पर

गुरिंदरवीर सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह पूरा लड्डू का डिब्बा खा जाएंगे। इसके बाद उन्होंने आलिया को एक जर्सी गिफ्ट की। फिल्म 'अल्फा' की बात करें तो इसे शिव रवेल ने डायरेक्ट किया है और यह यशराज स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म है। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ शरवरी, अनिल कपूर और बाँबी देओल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे, जबकि क्रतिक रोशन स्पेशल अपीयरंस में दिखाई देंगे। यह फिल्म 3 जुलाई 2026 को रिलीज होगी।

स्क्रीन टाइम नहीं, दमदार किरदार चाहिए : चेतना पांडे

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री चेतना पांडे को हालिया रिलीज फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' से दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस सफलता के बीच चेतना ने करियर, फिल्मों के चुनाव और भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब वह केवल ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहती हैं, जो उन्हें एक कलाकार के तौर पर आगे बढ़ाएं और दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ें। से बात करते हुए चेतना पांडे ने कहा, करियर के इस पड़ाव पर मैं खुद को किसी एक तरह के किरदार या फिल्म शैली तक सीमित नहीं रखना चाहती। हॉरर फिल्म में काम करने के बाद मुझे इस शैली की ताकत का एहसास हुआ है, इसलिए मैं आगे भी हॉरर फिल्मों में काम करना चांगूगी। मैं सिर्फ इसी शैली तक सीमित नहीं रहना चाहती। एक कलाकार के रूप में मेरा सबसे बड़ा सपना खुद को और अपने दर्शकों को लगातार नए रूप में चौंकाना है।

अभिनेत्री ने कहा, मैं ऐसा किरदार निभाना चाहती हूँ, जो मुझे भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौती दे और मुझे आगे बढ़ाता रहे। चाहे कोई बड़ी कमर्शियल फिल्म हो, थ्रिलर हो या फिर बायोपिक, मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने यह बात रखती है कि मेरा किरदार दर्शकों के मन में लंबे समय तक बना रहे। चेतना ने कहा, मुझे फिल्म में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए। मैं ऐसे रोल्स को प्राथमिकता देती



हूँ, जिनकी कहानी में दम हो और जो कुछ कहने की ताकत रखते हों। मैं केवल ग्लैमर दिखाने वाली भूमिकाओं की बजाय ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हूँ, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करें। हर नया प्रोजेक्ट मुझे पहले किए गए काम से आगे ले जाए और कुछ नया सिखाए। चेतना ने कहा, मैं अभी भी इस पूरे अनुभव को समझने और महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। जब कोई कलाकार लंबे समय तक किसी फिल्म पर मेहनत करता है, कई तरह की चुनौतियों का सामना करता है और यह उम्मीद करता है कि दर्शक उसके काम को पसंद करेंगे, तब सफलता मिलने के बाद उस पल को तुरंत समझ पाना आसान नहीं होता। 'हॉन्टेड 3डी' फिल्म की सफलता पर खुशी जताते हुए चेतना ने कहा, पिछले कुछ दिनों जश्न से ज्यादा आभास के रहे हैं। मैंने सबसे पहले परिवार, दोस्तों और उन लोगों से बात की, जिन्होंने इस सफर में हर कदम पर मेरा साथ दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे करीबी लोग मेरी सफलता से खुश हैं।

देश में 'रूफटॉप' सौर क्षमता बढ़ रही, लेकिन राज्यों में यह वृद्धि संतुलित नहीं : रिपोर्ट

नई दिल्ली/भाषा। देश में छतों पर लगने वाली सौर प्रणाली की क्षमता तेजी से बढ़ रही है लेकिन यह बढ़ती संतुलित नहीं है। ज्यादातर बढ़ती पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में हुई है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से अब भी काफी पीछे हैं। एक विश्लेषण में यह बात सामने आई है।

गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में मार्च तक छतों पर लगने वाली सौर ऊर्जा प्रणाली (रूफटॉप) की क्षमता क्रमशः 6,882 मेगावाट, 5,442 मेगावाट और 1,850 मेगावाट थी। वहीं, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम में यह क्रमशः 156 मेगावाट, 67 मेगावाट, 95 मेगावाट और 344 मेगावाट थी।

रिपोर्ट के अनुसार, इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अगर भारत 2035 तक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की उत्सर्जन तीव्रता में 47 प्रतिशत की कटौती और 60

प्रतिशत गैर-जीवाश्म-आधारित बिजली क्षमता की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहता है, तो हर राज्य को अपनी रूफटॉप सौर क्षमता बढ़ानी होगी।

बंगलूरु स्थित शोध और परामर्श संस्था क्लाइमेट कम्पैटिबल फ्यूचर्स (सीसीएफ) की रिपोर्ट के अनुसार, 'रूफटॉप सौर, बिना नई जमीन या पारेषण लाइन के मांग वाली जगह के पास साफ-सुथरी ऊर्जा क्षमता जोड़ने के सबसे तेज तरीकों में से एक है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जाए।' भारत की कुल रूफटॉप क्षमता मार्च तक 25.7 गीगावाट (एक गीगावाट बराबर 1,000 मेगावाट) तक पहुंच गई और अकेले 2026 की पहली तिमाही में 2.7 गीगावाट क्षमता जोड़ी गयी जो एक साल पहले की इसी तिमाही की तुलना में 125 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट के लेखकों के अनुसार, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल जैसे पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि उन्होंने कई साल पहले ही सौर प्रणाली लगाने से जुड़े नेटवर्क, वित्त पोषण चैनल और ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था।

एक और वजह यह है कि उनकी वितरण कंपनियां 'नेट-मीटरिंग एप्लिकेशन' को तेजी से प्रसंस्कृत करती हैं और रूफटॉप सौर को एक संपत्ति के तौर पर देखती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य कई वजहों से अब तक अपनी रूफटॉप सौर क्षमता बढ़ाने में नाकाम रहे हैं। 'पूर्वी क्षेत्र के अधिकतर हिस्सों में, आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना कर रही बिजली वितरण कंपनियां धीमी और अधिक सतर्क हैं। विक्रेताओं का आकार छोटा है और घरों को कर्ज मिलने में दिक्कत होती है और सब्सिडी के बारे में जानकारी भी कम है।'



सिंगापुर में होगी 'तुम से तुम तक' के खास ट्रैक की शूटिंग

मुंबई/एजेन्सी

टीवी का लोकप्रिय शो 'तुम से तुम तक' में एक नया और खास ट्रैक जुड़ने जा रहा है, जिसे लेकर शो की मुख्य अभिनेत्री निहारिका चौकर को काफी उत्साहित हैं। इस नए ट्रैक में उनके साथ अभिनेता शरद केलकर भी नजर आएंगे, और कहानी को एक नया मोड़ मिलेगा। से बात करते हुए निहारिका चौकर ने कहा, शो का आने वाला हनीमून ट्रैक मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि यह कहानी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह मोड़ मेरे किरदार 'अनु' और शरद केलकर के किरदार 'आर्य' की कहानी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इस ट्रैक में दोनों किरदारों को एक साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। निहारिका ने कहा, यह

कहानी का एक ऐसा हिस्सा है, जिसमें अनु और आर्य रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव से दूर, अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। इस दौरान उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और दर्शकों को उनके रिश्ते का एक नया पहलू देखने को मिलेगा।

उन्होंने कहा, दर्शकों का प्यार ही किसी कलाकार के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। अनु और आर्य की जोड़ी को दर्शकों से जो प्रतिक्रिया मिल रही है, वह पूरी टीम के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। इसी प्यार की वजह से टीम और मेहनत कर रही है ताकि कहानी को और बेहतर तरीके से पेश किया जा सके और दर्शकों को एक नया अनुभव मिल सके। उन्होंने बताया कि इस खास ट्रैक की शूटिंग के लिए पूरी

टीम जल्द सिंगापुर रवाना होने वाली है। यह शूटिंग जुलाई में होगी और लगभग एक हफ्ते तक चलेगी। विदेश में शूटिंग करना हमेशा एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि वहां का माहौल, लोकेशन और काम करने का तरीका सब कुछ नया होता है।

इस वजह से पूरी टीम में काफी उत्साह है और सभी लोग इस नए शेड्यूल को लेकर उत्सुक हैं। निहारिका ने कहा, जब टीम एक साथ किसी नए देश या जगह पर शूट करती है, तो उनके बीच की बॉन्डिंग भी और मजबूत हो जाती है। हालांकि ऐसे शेड्यूल थोड़े थकाने वाले जरूर होते हैं, लेकिन नए अनुभव और टीम के साथ बिताया गया समय इसे यादगार बना देता है।

मुझे महिलाओं का स्मोकिंग करना पसंद नहीं : शिल्पा शिंदे

मुंबई/एजेन्सी

आज के समय में 'फेमिनिज्म' शब्द लगातार चर्चा में रहता है। सोशल मीडिया से लेकर फिल्मों और इंटरव्यू तक, इसकी अलग-अलग परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। इस बीच अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने को दिए इंटरव्यू के दौरान इस पर अपनी अलग राय पेश की है। शिल्पा शिंदे ने कहा, मेरा मानना है कि असली पहचान बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि आत्मविश्वास, मूल्यों और खुद को समझने की क्षमता से होती है। यह जरूरी नहीं

है कि कोई महिला क्या पहन रही है या कैसे दिखती है, बल्कि वह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह अपने जीवन को कितनी स्पष्टता से समझती है। इसी बातचीत में शिल्पा शिंदे ने खुद को 'थोड़ा पारंपरिक सोच वाली' बताया। उन्होंने कहा, यह मेरी निजी सोच है कि मुझे महिलाओं का धूम्रपान करना पसंद नहीं है। कई लोग धूम्रपान या लाइफस्टाइल को मॉडर्निटी से जोड़ देते हैं, लेकिन मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। किसी आदत को मॉडर्निटी का पैमाना नहीं माना जा सकता। शिल्पा शिंदे ने आगे कहा,



मेरे लिए मॉडर्निटी का मतलब अलग है। सिर्फ धूम्रपान करना,

शराब पीना या अलग तरह के कपड़े पहनना किसी को बोल्ट नहीं बनाता।

असली बोल्टनेस वह है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों पर मजबूत हो, अपने फैसलों को समझता हो और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता हो। बाहरी दिखावा और असली व्यक्तित्व दो अलग चीजें हैं, जिन्हें अक्सर लोग गलत तरीके से जोड़ देते हैं। शिल्पा शिंदे ने कहा, कपड़े और सोच का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं होता। किसी व्यक्ति की मानसिकता उसके पहनावे से तय

नहीं होती। कोई व्यक्ति साड़ी पहनकर भी मॉडर्न सोच रख सकता है और कोई मॉडर्न कपड़े पहनकर भी पुराने विचारों वाला हो सकता है। इसलिए किसी को उसके कपड़ों से जज करना सही नहीं है। शिल्पा शिंदे ने कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से साड़ी पहनने वाली महिलाएं ज्यादा पसंद हैं, लेकिन यह मेरी फैशन या पसंद की बात है, न कि सोच की। एक महिला के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि वह खुद को समझे, अपने मूल्यों को जाने और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीए। यही सही मजबूती है।

